कश्मीर में उम्मीद

केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की लगातार कोशिशों के बावजूद कश्मीर में हिंसा रोकने की चुनौती बनी हुई है. ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से यह इंगित होता है कि उनके एजेंडे में कश्मीर ऊपर है. इस दौरे से उम्मीदें इस वजह से भी बढ़ गयी हैं कि अलगाववादियों ने किसी तरह के बंद या विरोध का आयोजन नहीं किया. तीन दशकों से अशांत घाटी में ऐसा पहली बार हुआ है. आतंकियों के हाथों मारे गये लोगों के परिजनों तथा विभिन्न समुदायों और संगठनों के प्रतिनिधियों से गृह मंत्री की मुलाकात से भी भरोसे बनाने में मदद मिलेगी. साल 2014 से ही कश्मीर घाटी में विकास की गति तेज करने तथा लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं. फिर भी, 2018 में दस सालों में सबसे अधिक मौतें हुई थीं और यह सिलसिला इस साल भी जारी है. इस महीने की 17 तारीख तक दो सौ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. हालांकि, इन आंकड़ों में आतंकियों की तादाद बहुत है, फिर भी सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की जानें भी जा रही हैं. यह भी सच है कि पाकिस्तान द्वारा पाले-पोसे और बरसों से चल रहे आतंकवाद से निजात पाने में अभी वक्त लगेगा. एक तरफ गृह मंत्री ने जहां विकास कार्यों की समीक्षा की है, वहीं उन्होंने आतंक के खिलाफ सख्त रवैया बरकरार रखने का भी निर्देश दिया है. कश्मीर समस्या का समाधान निकलने की दिशा में प्रगति की आशा बंधने का एक आधार जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का बयान है कि अलगाववादी समूह हुर्रियत बातचीत के लिए तैयार है. हुर्रियत के रुख में बदलाव के अनेक कारण हैं. भारत के कूटनीतिक प्रयासों से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान को आर्थिक तबाही से बचाने में मदद दे रही संस्थाएं भी कह रही हैं कि वह अपनी धरती पर सक्रिय चरमपंथी और हिंसक गिरोहों पर लगाम लगाये. अलगाववाद और आतंकवाद के विरुद्ध केंद्र की कठोर नीतियों ने भी हुर्रियत को यह अहसास दिला दिया है कि उनके पास बातचीत के अलावा विकल्प नहीं बचा है. इस साल सौ से अधिक आतंकियों का सफाया तथा अलगाववादी नेताओं पर जांच का कसता शिकंजा केंद्र के रवैये के साफ संकेत हैं. सुरक्षा कारणों से लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभा के चुनाव नहीं हो सके थे. अब चुनाव आयोग इसके लिए तैयार है. हुर्रियत को यह भी अहसास है कि राज्य में निर्वाचित सरकार स्थापित होने के बाद बातचीत का हिसाब बदल जायेगा तथा कश्मीरियों का प्रतिनिधित्व करने का उसका दावा और भी कमजोर पड़ जायेगा. पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ घाटी के लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और आम कश्मीरी अपने युवाओं को हिंसा की राह में भटककर मौत के मुंह में जाते नहीं देखना चाहता है. नौजवानों के बड़े हिस्से को भी विकास में भविष्य नजर आ रहा है. बदलते हालात में कश्मीर में बदलाव की बयार बह सकती है और गृह मंत्री शाह के दौरे को इसकी शुरुआत माना जा सकता है.

अमित शाह के कश्मीर दौरे से उम्मीदें इस वजह से भी बढ़ गयी हैं कि अलगाववादियों ने कोई विरोध नहीं किया. तीन दशकों से अशांत घाटी में ऐसा पहली बार हुआ है.

भारत-अमेरिकी संबंध की दिशा

पुष्पेश पंत
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
pushpeshpant@gmail.com

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का भारत दौरा उस वक्त संपन्न हो रहा है, जब भारत और अमेरिका के संबंध काफी असहज हैं. छोटे-बड़े अनेक मतभेद अंतरराष्ट्रीय सामरिक परिप्रेक्ष्य और उभयपक्षीय राष्ट्रहितों के टकराव के कारण प्रकट हो रहे हैं. पिछले लगभग तीन दशक से भारत और अमेरिका के संबंध क्रमशः प्रगाढ़ और गुटनिरपेक्षता के युग वाला परस्पर अविश्वास पूरी तरह मिट चुका था. जब से भारत ने आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया है, अमेरिका के साथ पूंजीवाद बनाम समाजवाद जैसी सैद्धांतिक बहस बेमानी हो गयी है. खासकर जब यूपीए के कार्यकाल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परमाण्विक ऊर्जा के शांतिपूर्ण करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी सरकार दांव पर लगा दी थी, तब से आम भारतीय सोचता आ रहा है कि भारत अमेरिका के बहुत करीब है. गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मास्टर कार्ड जैसी बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी भारतवंशी ही हैं. पहले कार्यकाल में मोदी की अमेरिका यात्रा और तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के साथ उनकी आत्मीय दोस्ती ने इस मान्यता को पुष्ट किया कि दोनों देशों के बीच मनमुटाव नहीं है. फिर क्या कारण है कि पॉम्पियो की यात्रा को लेकर गंभीर आशंकाए मुखर हो रही हैं?

भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ पॉम्पियो ने जो संयुक्त बयान जारी किया है, उसमें राजनयिक शब्दाडंबर के बावजूद इस बात को छुपाया नहीं जा सका कि दोनों देशों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर मतभेद बरकरार हैं. पॉम्पियो ने कहा कि दुनिया में कोई भी देश चाहे कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हों, उनके बीच कुछ ना कुछ मतभेद बचे रहते हैं और यह स्वाभाविक ही है. संवाद से इनका समाधान निकाला जाता है यही जनतांत्रिक राजनयी की खूबी है. जयशंकर ने इसी सच को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया और इस बात के लिए अमेरिका का आभार प्रकट किया कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में आवागमन को आबाद रखने में भारत के साथ सहयोग कर रहा है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध उसकी सहायता के लिए तत्पर रहा है. पर जब प्रेस सम्मेलन में यह प्रश्न पूछा गया कि क्या ईरान के चाबहार बंदरगाह के विषय में कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि फिलहाल इस बारे में कोई टकराव नहीं है. फिलहाल भले ही ट्रंप का अमेरिका चाबहार को भारत के साथ विवाद का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, भविष्य में वह ऐसा कर सकता है. यह बात रेखांकित करना जरूरी है कि पॉम्पियो ने ईरान को दुनियाभर में आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक घोषित किया है. अमेरिका की नजर में ईरान आतंकवादी हो सकता है, पर भारत इस राय से सहमत हो, यह जरूरी नहीं. भारत जिस कट्टरपंथी जेहादी आतंकवाद का शिकार है उसका प्रायोजक ईरान नहीं, बल्कि अमेरिका का मित्र सऊदी अरब है. सऊदी से ही पाकिस्तान को संरक्षण, सहायता और प्रोत्साहन मिलता रहा है.

पश्चिम एशिया की रणभूमि में अमेरिका जिन तत्वों के साथ है, उनके खिलाफ रूस, ईरान और लेबनान तथा कुर्द खड़े हैं. यहां बुनियादी टकराव यमन से लेकर सूडान तक सुन्नी सऊदी अरब और शिया ईरान के बीच है. ऊर्जा सुरक्षा अर्थात तेल की राजनीति में भी यह द्वंद्व सऊदी अरब और ईरान के बीच है. सद्दाम हुसैन के खात्मे के बाद इराक के तेल कूपों को हथियाने के बाद अमेरिका की रणनीति ईरान को एक तेल निर्यातक शक्ति के रूप में ध्वस्त करने की है, ताकि सऊदी अरब की मदद से वह और उसका बगल बच्चा इस्राइल यूरोप पर अपना प्रभुत्व उनकी तेल आपूर्ति को नियंत्रित कर अच्छी तरह कर सकता है. जयशंकर ने भारतीय हितों को अमेरिकी हितों से अलग करते हुए यह जोड़ना जरूरी समझा कि ईरान के साथ भारत के संबंध सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं. इसके दूसरे ऐतिहासिक-सांस्कृतिक आयाम भी हैं.

मध्य एशिया की राजनीति में चीन ही भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है. वह जिस ऐतिहासिक रेशम राजमार्ग के पुनर्निर्माण से ग्वादर के पोत तक पहुंचना चाहता है, वह वास्तव में दक्षिण एशिया में भारत की घेराबंदी और प्रकारांतर से रूस को बचाव की मुद्रा में रहने को विवश करने का प्रयास है. जहां अमेरिका अपनी सामरिक नीति के अनुसार भारत को अफगानिस्तान के दलदल में धंसाना चाहता है, वहीं भारत ईरान में चाबहार तक अपनी पहुंच बढ़ा रूस के साथ उस उत्तर-दक्षिण गलियारे को वन बेल्ट वन रोड के मुकाबले खड़ा करना चाहता है, जिसकी चर्चा यूपीए के पहले कार्यकाल में मनमोहन सिंह के पलटी खाने के पहले काफी गर्म थी. तब अजरबैजान से भारत तक लायी जानेवाली तापी गैस पाइपलाइन लाने का शोर मचा. पता नहीं क्यों आज रूस के साइबेरिया क्षेत्र में उस सखालिन तेल-गैस निवेश को हम एकदम भूल गये हैं, जिसमें भारत ने कई अरब डॉलर लगाये थे.

अमेरिका को आज उस सैनिक साज-सामान की खरीदारी को लेकर भी सिरदर्द है, जो भारत रूस से कर रहा है. पश्चिम एशिया में पुतिन की दुस्साहसिक नीतियों को देखते हुए और उक्रेन में सैनिक हस्तक्षेप के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाये हैं. पर ट्रंप के लिए यह समझना परमावश्यक है कि आधी सदी से भी अधिक समय से भारत सैनिक साज-सामान की खरीदारी रूस से करता रहा है. मोदी कार्यकाल में भारत ने रूस से इतर विकल्प तलाशने शुरू किये हैं. जिनमें फ्रांस से राफेल और इस्राइल से परिष्कृत टेक्नोलॉजी का आयात शामिल है.

कुछ छोटे-छोटे मुद्दे हैं, जिन पर अमेरिकी रियायत कर भारत को बड़ी रियायत के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहे हैं. एच1-बी वीजा की संख्या बढ़ाने से कुछ खास हासिल होनेवाला नहीं. जब तक अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद निर्बाध रूप से नहीं पहुंचते, तब तक अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं के लिए अपना बाजार खोलने की भारत की मजबूरी नहीं होनी चाहिए. ट्रंप विश्व व्यापार संगठन को नष्ट करने की धौंस-धमकी दे अमेरिकी बाजार को संरक्षित रखना चाहते हैं. पर चीन के साथ वाणिज्य युद्ध की घोषणा कर उन्होंने अपने लिए विकट चुनौती पैदा की है. भारत-अमेरिकी संबंध अंततः विदेश मंत्री स्तर के संवाद से तय होनेवाले नहीं. जी-20 सम्मेलन के अवसर पर शी, आबे और पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात ही इस बात का फैसला करेगी कि ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री पर कितना दबाव बना सकते हैं? अंत में याद रखें- शक्तियों के संबंध व्यक्तिगत दोस्ती पर नहीं, राष्ट्रहितों के अनुसार ही समायोजित होते हैं.

भारत-अमेरिकी संबंध अंततः विदेश मंत्री स्तर के संवाद से तय होनेवाले नहीं. जी-20 सम्मेलन के अवसर पर शी, आबे और पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात ही यह फैसला करेगी कि ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री पर कितना दबाव बना सकते हैं?

सोने में तूफानी तेजी का परिदृश्य

डॉ जयंतीलाल भंडारी
अर्थशास्त्री
jlbhandari@gmail.com

इन दिनों पूरी दुनिया में सोने में तूफानी तेजी का परिदृश्य दिख रहा है और सोने की कीमतें छह साल की ऊंचाई पर पहुंच गयी हैं. इसके चार प्रमुख कारण हैं. एक, दुनिया के केंद्रीय बैंकों के द्वारा डॉलर की तुलना में सोने को महत्व दिया जा रहा है और वे सोने की खरीदी बढ़ा रहे हैं. दो, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से युद्ध की आशंका बढ़ गयी है. तीन, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार के कारण वैश्विक मंदी का डर सता रहा है. ऐसे में निवेशक सोने की खरीदी को उपयुक्त मान रहे हैं. चार, अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना से डॉलर कमजोर हुआ है और इससे सोने की चमक तेज हुई है.

गौरतलब है कि पूरी दुनिया के अधिकतर केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही सोने की अधिक खरीदी के कारण सोने की कीमतें सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच गयी हैं. जून 2015 में सोने की जो कीमतें करीब 1,070 डॉलर प्रति औंस थी, वह जून 2019 में करीब 1,400 डॉलर प्रति औंस के पार हो गयी है. भारत में 26 जून, 2019 को सोने की कीमत 35 हजार 960 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गयी है. सोने की अधिक कीमत हो जाने के कारण लोगों के द्वारा पुराने सोने तथा गहनों की बिक्री बढ़ गयी है. रूस, चीन और भारत सहित दुनिया के कई देशों के केंद्रीय बैंकों ने पिछले कुछ महीनों में काफी मात्रा में सोना खरीदा है. कुल 613 टन सोने के भंडार के साथ आरबीआइ 10वां सबसे बड़ा सोना भंडार वाला केंद्रीय बैंक है. वेस्ट गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में केंद्रीय बैंकों की सोने की मांग कई दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी है.

सोने की कीमतों में नयी तेजी की जड़ें दुनिया के कई विकसित देशों द्वारा डॉलर के नये विकल्प की तलाश में आगे बढ़ना भी है. अमेरिकी डॉलर की तुलना में सोना खरीदने पर चीन अधिक जोर दे रहा है. कच्चे तेल के भंडार रखनेवाले कई खाड़ी देश भी सोना खरीद रहे हैं. यद्यपि अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार पेट्रो डॉलर है, लेकिन डॉलर के विकल्प बहुत तेजी से उभर रहे हैं. ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की तुलना में सोना अधिक लाभकारी दिख रहा है.

अमेरिका आनेवाली हर बाहरी वस्तु पर जिस तरह आयात शुल्क बढ़ा रहा है, उसने दुनिया के कई देशों को डॉलर केंद्रित व्यवस्था से दूरी बनाने के लिए प्रवृत्त कर दिया है. ऐसे में निकट भविष्य में सोना मजबूत बना रह सकता है. चीन तथा रूस के साथ अमेरिका का विरोध करनेवाले देशों के द्वारा डॉलर की धार को मंद करना भी सोने की कीमतों की तेजी एक वजह है. ये देश डॉलर की तुलना में सोने को महत्व दे रहे हैं तथा बिक्री के लिए उपलब्ध सोने में से खूब सोना खरीद रहे हैं.

भारत में सोने की बढ़ती मांग बता रही है कि एक बार फिर भारत के अधिकांश बचतकर्ता सोने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. सोने की कुल वैश्विक मांग का एक तिहाई भारत में है. भारत में सोने की 90 फीसदी मांग आभूषणों या भगवान को चढ़ाने के लिए होती है. सोने के आभूषण पहनना हमारी संस्कृति का अंग भी है. सोने में अमीरों द्वारा किये जानेवाले निवेश के साथ गरीबों की ओर से भी लगातार ज्यादा निवेश किया जा रहा है. वे भी अपनी छोटी-छोटी बचतों से सोने की छोटी-छोटी वस्तुएं खरीदते हैं. प्रतिवर्ष देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का तीन फीसदी सोने के रूप में कम उत्पादक पूंजी में बदल रहा है. यदि हम यह सोचकर बढ़ती हुई सोने की मांग को खारिज कर दें कि सोने को लेकर भारतीयों की कमजोरी पुरानी है, तो हमारा यह विश्लेषण गलत होगा. आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे देश में जब भी अधिक उपयोगिता दिखती है, तब सोने की मांग बढ़ती है तथा आयात भी बढ़ता है.

हमारे देश में इस समय सोने की खरीदी बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि विभिन्न बचत योजनाओं में बचत करनेवालों को समुचित प्रतिफल हासिल नहीं हो रहा है. बीते 24 जून को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने संकेत दिये कि विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में और कमी की जायेगी. अब भी देश के ज्यादातर लोग शेयर बाजार में निवेश से दूर हैं. उन्हें यह साफ नजर आ रहा है कि सोने में निवेश किसी अन्य बचत योजना की तुलना में अधिक लाभप्रद होगा.

भारत जैसे विकासशील देश के लिए सोने में निवेश उत्पादक नहीं है. ऐसे में सोने की मांग घटाने के सार्थक प्रयास किये जाने जरूरी हैं. हमारे देश में जो बचत अब भी सामाजिक सुरक्षा का प्रमुख आधार बनी हुई है, वह बचत कम ब्याज दर से घटती जा रही है. सोने में निवेश करनेवालों के कदम शेयर बाजार की ओर मोड़ने के लिए लोगों का शेयर बाजार में विश्वास बढ़ाना होगा. भारत के शेयर और पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि सेबी शेयर बाजार की गतिविधियों पर सतर्कता से ध्यान देकर उसे स्वस्थ दिशा प्रदान करे और शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

हम आशा करें कि सरकार देश में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते ट्रेड वार की चिंताओं, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की बढ़ती चिंताओं और दुनिया के विभिन्न केंद्रीय बैंकों के द्वारा सोने की बढ़ती हुई खरीदारी के बीच देश के उपभोक्ताओं द्वारा सोने की मांग की चिंताओं को समझकर मांग घटाने के लिए विभिन्न बचत एवं निवेश योजनाओं को इस तरह आकर्षक एवं सुरक्षित बनायेगी कि बचत करनेवालों को समुचित प्रतिफल मिले और बचतकर्ता के कदम सोने की खरीदी की बजाय बचत योजनाओं में निवेश की डगर पर आगे बढ़ें.

एक बार फिर भारत के अधिकांश बचतकर्ता सोने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. लेकिन, भारत जैसे विकासशील देश के लिए सोने में निवेश उत्पादक नहीं है. ऐसे में सोने की मांग घटाने के सार्थक प्रयास किये जाने जरूरी हैं.

बोधि वृक्ष

द्वंद्व और प्रतिरोध

बातों, तर्क-वितर्क और व्याख्याओं का कोई अंत नहीं होता. लेकिन व्याख्याएं, तर्क-वितर्क और बातें, हमें किसी सीधी कार्यवाही तक नहीं ले जाते, क्योंकि सीधी कार्यवाही, सीधे तुरंत कर्म तक पहुंचने के लिए हमें मौलिक और आधारभूत रूप से बदलने की आवश्कता होती है. यदि शब्दों की गहराई से सोचें, तो इसके लिए किसी भी तर्क-वितर्क, लफ्फाजी, ना बहलाने-फुसलाने, ना किसी सूत्र, ना किसी से प्रभावित होने की आवश्यकता होती है कि हम मूलभूत रूप से बदल सकें. हममें बदलाव की आवश्कता तो है, लेकिन किसी विशेष संकल्पना या सिद्धांत के अनुसार नहीं, क्योंकि जब हमारे पास किसी कर्म के बारे में कोई विचार या धारणा होती है, तो कर्म चुक जाता है. कर्म और विचार या धारणा के बीच एक समय अंतराल होता है, एक स्थगन/देरी होती है और इस समय अंतराल में उस विचार/धारणा के प्रति या तो प्रतिरोध होता है, या सुनिश्चितता या किसी विचार या धारणा की नकल और उसे कर्म में बदलने की कोशिश. यही सब हम में से अधिकतर लोग, हमेशा करते रहते हैं. हम जानते हैं कि हमें बदलना है, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि गहरे तक- मनोवैज्ञानिक रूप से. बाहरी बदलाव तो बहुत से हैं. वे हमें किसी कार्य प्रणाली/किसी तौर तरीके के अनुसार सुनिश्चित होने के लिए या कहें कि एक ढर्रे पर चलने के लिए बाध्य करते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हममें गहन क्रांति की आवश्यकता होती है. हममें से अधिकतर के पास कोई न कोई पूर्वनिर्धारित विचार या धारणा होती है कि हमें क्या होना चाहिए, परंतु हम कभी बुनियादी तौर से नहीं बदल पाते. हमें क्या होना चाहिए- इस संबंध में विचार और मनोभाव हममें कोई परिवर्तन नहीं ला पाते. हम तभी बदलते हैं, जब यह नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम परिवर्तन की आवश्यकता को कभी सीधे-सीधे अपने सामने, साक्षात् नहीं देख पाते. हम कभी बदलना भी चाहते हैं, तो हममें भारी द्वंद्व और प्रतिरोध खड़ा हो जाता है और हम प्रतिरोध करने में.

जे कृष्णमूर्ति

आपके पत्र

स्वास्थ्य ढांचे को बनाएं मजबूत

कई बार किसी बीमारी के मूल कारणों का पता लगाना मुश्किल होता है, किंतु यदि उससे बचाव और उपचार के बेहतर उपाय किये जा सकें तो हालात काबू करने में मदद मिलती है. बिहार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सवालों का चाहे जो जवाब दें, यह सच्चाई है कि मुजफ्फरपुर का श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं दिखा. ऐसा तब हुआ, जब यह उत्तरी बिहार का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है और कई वर्षों से एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मरीजों का गवाह बनता रहा है. संसाधनों के अभाव का सामना कर रहा यह अस्पताल देश में सरकारी स्वास्थ्य ढांचे की खराब स्थिति को ही बयान करता है. आवश्यक केवल यही नहीं है कि बिहार में बच्चों की मौत का सिलसिला थमे, बल्कि यह भी है कि केंद्र और राज्य सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कमर कसें.

डॉ हेमंत कुमार, गोराडीह, भागलपुर

धार्मिक विद्वेष खत्म हो

अभी पांच दिन पहले ही अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत में धार्मिक भेदभाव का चलन बढ़ने का आरोप लगाया. हमारे विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तत्काल इन आरोपों को खारिज कर दिया. मगर कल वहां के विदेश मंत्री भारत आकर, हमारे विदेश मंत्री के सामने भारत को धार्मिक अधिकारों का पालन करने को कह दिया. क्या सिर्फ नकार देने से यह आरोप गलत साबित हो जायेगा? भीड़ द्वारा तुरंत उसी स्थान पर मौत की सजा देने की प्रथा जोरों से चल पड़ी है. जब प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपति थे तब उन्होंने दो बार सरकार को आगाह किया था. उसके बाद प्रधानमंत्री ने पहले भी और कल भी, संसद में झारखंड में हुई तबरेज अंसारी की हत्या की निंदा की. सिर्फ झारखंड में ही पिछले तीन वर्षों में 11 लोगों की भीड़ द्वारा हत्या की गयी है. अगर सबसे बड़ा लोकतंत्र वाले देश का यह हाल रहेगा, तो अमेरिका क्या कोई भी भारत पर उंगली उठा सकता है. किस-किस के आरोपों को हम खारिज करते रहेंगे ?

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी,जमशेदपुर

दबाव उचित नहीं !

ताजा लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शायद अपनी गलतियों को देखते हुए त्यागपत्र पर अड़े हैं, मगर परिवार और पार्टी के कुछ वफादार और प्रिय जन इसके खिलाफ धरने, प्रदर्शन और अनशन आदि से दबाव बनाये हुए हैं जो उचित नहीं है. क्या पार्टी में और अच्छे नेताओं की कोई कमी है, शायद नहीं. यदि राहुल चाहें तो प्रियंका और सोनिया गांधी आदि बड़े नेताओं से मिलकर किसी को भी यह दायित्व सौंप सकते हैं. कोई इंसान और परिवार कभी बुरा नहीं होता. कुर्बानी, त्याग भावना और अच्छे कार्यों से ही आगे बढ़ा जा सकता है. इसलिए अब पार्टी को खुलकर और सकारात्मक सोच से ही आगे बढ़ना होगा. अब संभलने और सुधरने का वक़्त है. आशा है पार्टी कुछ सही सोचकर ही अब आगे बढ़ेगी.

वेद मामूरपुर ,नरेला

कुछ अलग

पानी जब कर दे पानी-पानी !

संतोष उत्सुक
वरिष्ठ व्यंग्यकार
santoshutsuk@gmail.com

पानी की बढ़ती कमी के कारण मानवता पानी-पानी हो रही है. 'नानी याद आना' मुहावरा जगह-जगह बह रहा है. स्वार्थ की जुगाड़-जंग जारी है. जिसे आराम से पानी मिल जाता है, चुप रहता है. व्यवस्था को नहीं कोसता, पड़ोसी को भी नहीं बताता. डरता है, आता-जाता कहीं मिल गया, तो आधी बाल्टी पानी मांग ही लेगा. पानी के लिए लाइनें लगी हैं, साफ पानी किसे मिलेगा, के लिए अमेरिकी वीजा की तरह लॉटरी सिस्टम फैसला कर रहा है. तालाबों को दफन करने के बाद अब यज्ञ किये जा रहे हैं. ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं. विधायक विधेयक लाने के प्रयास कर रहे हैं, काश वे जादूगर होते, लोगों को हिप्नोटाइज करते और उन्हें लगता हमारे पास बहुत पानी है. लेकिन असलियत का सांप सिहरन पैदा कर देता है.

जनता को हो रही पानी की किल्लत को खबर बनाते हुए बचे-खुचे प्रखर पत्रकार ने प्रशासनिक कुव्यवस्था पर उबलता पानी उड़ेला. लिखा कि पानी की कमी वीआईपी व गणमान्य लोगों को पानी-पानी नहीं कर सकती है. उनकी कारें, लान व कुत्ते रोज नहाते हैं और कई बस्तियों में कई दिन के बाद भी पानी नहीं आता. एक बाल्टी पानी से पहले परिवार का एक आदमी नहाता है, फिर दूसरा और तीसरा. इसी पानी से कपड़े धोये जा रहे, बर्तन मंज रहे हैं. मंत्रीजी यह समझा रहे हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगायें, ताकि परसों बादल आकर बारिश कर दें. पत्रकार रात को घर जा रहे थे. आईपीएच विभाग के छोटे अफसर थकावट के कारण, कड़वा पानी पिये मिल गये. बात होने की सही स्थिति थी, तो वे बोले, आज हमारे विभाग की जड़ों में खूब तेल डाला. पत्रकार ने पूछा कि जनता परेशान वीआईपी मजे में हैं, आप पानी का प्रबंधन ठीक क्यों नहीं करते? झूठ बोलने की अवस्था न होने के कारण अफसर बोले, बड़े लोगों के साथ रिश्तों को जिन तरल चीजों से सींचना पड़ता है, आजकल पानी उनमें से खास है. पानी आजकल के सूखे मौसम में ट्रांसफर भी करवा सकता है. इंडिया के 'वेरी इंडिफरेंट पर्सन' को सब कुछ चाहिए, भले किसी और को कुछ मिले न मिले.

पानी को अभी भी हम आम वस्तु समझते हैं. उसे बरबाद करते हैं. यह आम वस्तु खास लोगों को खूब चाहिए. पानी बिना कुत्ते, फर्श, गार्डन, लॉन, रास्ता व बैडमिंटन कोर्ट कैसे धुलेगा. कम में काम चल सकता है, लेकिन लाल बत्ती उतरने से क्या फर्क पड़ता है. हमारे 'वेरी इंटेलीजेंट पर्सन' को सभी निजी काम सही तरीके से करने आते हैं. रोज न नहायें और धुले कपड़े न पहनें, तो 'वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन' ताजादम फील नहीं करते. तरोताजा नहीं होंगे, तो आम जनता का इतना काम कैसे करेंगे. इसलिए पानी की सप्लाई उनके यहां जरूरी है. किट्टी पार्टी में शान से बताना पड़ता है, हमारे यहां तो पानी की कोई कमी नहीं है. 'वेरी इंडियन पर्सन' को ऐसा ही होना चाहिए. आईपीएच वाले भैया की बात में गहरा पानी है. यह आम आदमी की हिम्मत है कि पानी बिना भी जिंदगी की मछली पकाता है. जो स्वयं मछली हैं, वे पानी के बाहर कैसे आ सकते हैं.

देश दुनिया से

जापान के ओसाका में जी20 शिखर सम्मेलन

जापान के ओसाका में हो रहा जी20 शिखर सम्मेलन सबसे ज्यादा विखंडित दुनिया के विरोधाभासों को एक साथ एक मंच पर ला रहा है. मध्य-पूर्व या पश्चिम एशिया में उथल-पुथल मची हुई है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद दुनिया के अनेक क्षेत्रों में एक विघटनकारी मुद्दा बना हुआ है. इसी बीच चीन पर अमेरिकी हमले हो रहे हैं और उसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन मिल रहा है. जी20 विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधिक राजनीतिक समूह है. इसी वर्ष सितंबर में यह 10 वर्ष का हो जायेगा. यह समूह वैश्विक जीडीपी के 80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है. साल 1990 में हुए वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया में स्थापित यह समूह मौजूदा सांस्थानिक संरचना के भीतर सर्वाधिक जनसंख्या वाले विकासशील देशों को विस्तृत प्रतिनिधित्व देता है. सम्मेलन की कार्यसूची व्यापक है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था से लेकर व्यापार, रोजगार, स्वास्थ्य, नवाचार, विकास व पर्यावरण तक के मुद्दे शामिल हैं. जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे आगामी चुनाव के मद्देनजर इस शिखर सम्मेलन का लाभ लेने के लिए 'ओसाका ट्रैक' को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. उनका ध्यान सोसाइटी 5.0 (पोस्ट-इंडस्ट्रियल) बनाने के लिए नवाचार पर होगा.

GLOBAL TIMES

फैबियो मास्सिमो पैरेंटी

कार्टून कोना

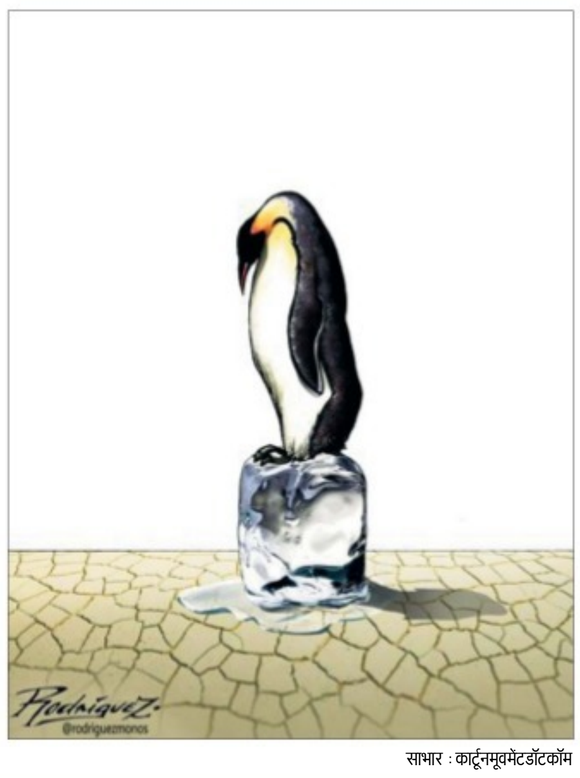

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है